आईआईबीएफ विज़न फरवरी, 2012

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 8 मार्च 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------2
विनियामकों के कथन ----------4
बीमा ----------4
सूक्ष्मवित्त ----------5
अर्थव्यवस्था ----------5
विदेशी मुद्रा ----------5
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में एक : "दि इकॉनॉमिस्ट"

"दि इकॉनॉमिस्ट" पत्रिका ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को विश्व के सर्वश्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकों में से एक तथा भारत की उत्तम संस्थाओं में से एक के रूप में वर्णित किया है। संख्याओं के आधार पर निर्णय लिये जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक विश्व के सर्वश्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकों में से एक है। वृद्धि और मुद्रास्फीति को संतुलित रखने के सम्बन्ध में उसका रिकार्ड पर्याप्त रूप से शालीन है। 1995 से थोक मूल्यों में प्रति वर्ष 6% के औसत से वृद्धि हुई है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के लगभग 5% के सहूलियत के स्तर से बहुत अधिक नहीं है। वृद्धि का औसत प्रति वर्ष 7% रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा का भी प्रभारी है। इस क्षेत्र में उसका रिकार्ड उत्कृष्ट रहा है। चालू खाते के उस घाटे के बावजूद, जो भारत को वैश्विक हड़बड़ी के प्रति असुरक्षित बना देता है, देश 1997 के एशियाई संकट (एक भूतपूर्व गवर्नर याद करते हैं "किसी ने हमे मौका नहीं दिया") और 2008 में पश्चिमी देशों के बैंकिंग संकट से बच निकला। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाल स्ट्रीट के लड़खड़ाने की शुरूआत होने से पहले वाले उल्लासोन्मादात्मक वर्षों में भारी और संभाव्य रूप से अस्थिरकारी पूंजी अन्तर्वाहों का भी मुकाबला किया तथा कई वर्षों तक बैंकों की आस्तियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद घरेलू वित्तीय संकट को टालने में कामयाब रहा।

अब तक का सबसे पहला ई-चेक

ब्रिटिश शोधकर्ताओं के एक दल ने अब तक का सबसे पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चेक (ई-चेक) विकसित करने का दावा किया है, जो पारंपरिक प्रणाली का लाभ तो प्रदान करता ही है, अपितु बैंकों की संसाधन और परिवहन लागत में भी काफी कमी ला देता है। नूतन-प्रौद्योगिकी वाली यह चेक-बुक देखने और कार्य करने में प्राय: परंपरागत चेक-बुक जैसी ही होती है, किन्तु उस पर लिखने के लिए एक ऐसी डिजिटल कलम की जरूरत पड़ती है, जिससे उसके अग्रभाग पर मुद्रित मिलियनों की संख्या में नन्हें-नन्हें बिन्दुओं पर किए जाने वाले किसी भी आघात को रिकार्ड करने के लिए एक बहुत छोटा-सा कैमरा जुड़ा हो। उक्त कलम विवरणों को एक बेतार संपर्क के माध्यम से ग्राहक के बैंक को

भेजता है। चूंकि चेक और डिजिटल कलम केवल ग्राहक के अपने सुरक्षित कम्प्यूटर हब के साथ काम करते हैं, उन्हें चोर से सुरक्षित कहा जाता है। परंपरा और आधुनिकता का संयोजन करते हुए यह बैंकों के लिए सुरक्षित और सस्ता इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन और उसके बावजूद ग्राहक के लिए एक भौतिक कागज़ आधारित लेनदेन है।

नेशनल आस्ट्रेलियन बैंक बैंक का भारत में पदार्पण

अपनी समग्र एशिया रणनीति के अनुरूप नेशनल आस्ट्रेलियन बैंक (NAB) ने अब भारत में प्रवेश करते हुए 2011 में अपने चीन में पदार्पण का अनुसरण किया है। मुंबई में स्थित उसकी पहली शाखा भारत में परिचालनरत अथवा उसके साथ व्यापार करने वाली संस्थागत कम्पनियों और व्यवसाय बैंकिंग ग्राहकों की सहायता करेगी। बैंक आस्ट्रेलिया अथवा न्यूजीलैंड में विशेषत: ऊर्जा, शिक्षा और कृषि-व्यवसाय क्षेत्रों में विस्तार या निवेश करने के इच्छुक भारतीय ग्राहकों के साथ समन्वय करेगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

बासेल-III ढांचे के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का प्रारूप

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि जोखिम प्रबन्धन और चलनिधि मानकों के बारे में बासेल-III ढांचे सें सम्बन्धित दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी कर दिया है। इन दिशानिर्देशों में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BSBC) द्वारा जारी बासेल-III नियमों के पाठ में यथा-वर्णित दो ऐसे न्यूनतम वैश्विक विनियामक मानक यथा - चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) और निवल स्थायी निधीयन अनुपात (NSFR) निर्धारित किए गए हैं, जो क्रमश: 1 जनवरी, 2015 और 1 जनवरी, 2018 से बाध्यकर होंगे। तब तक इन दिशानिर्देशों को उत्तम प्रयास के आधार पर अनुपालन के लिए जारी किया गया है।

कृषि उधार : भारतीय रिज़र्व बैंक का पैनल उप-लक्ष्यों को समाप्त करने का पक्षधर

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य दल ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के लिए उप-लक्ष्यों को समाप्त किए जाने की सिफारिश की है। श्री एम.डी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाले उक्त कार्य दल ने इसके बजाय केवल लघु एवं सीमांत श्रेणी में आने वाले किसानों को उधार देने हेतु ही उप-लक्ष्यों की सिफारिश की है। इसके अलावा, वह ग्रामीण मूलभूत सुविधा स्थापित करने हेतु ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में वर्गीकृत किए जाने के पक्ष में है।

बैंकों से बचत जमा दर की गणना दिवसांत (EoD) शेष पर करने के लिए कहा गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से बचत जमा पर ब्याज दर की गणना ग्राहक के खाते में दिवसांत पर शेष राशि पर करने के लिए कहा है। 1 लाख रुपये तक के दिवसांत शेष पर बैंकों से उनके द्वारा नियत एकसमान दर लागू किया जाना अपेक्षित है। 1 लाख रुपये से अधिक के दिवसांत शेष के मामले में बैंक उनके द्वारा नियत विभेदक दर (दरें) लागू कर सकते हैं।

1,700 करोड़ रुपये की अदावीकृत जमाराशियां वापस करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से लगभग 1,700 करोड़ रुपये की अदावीकृत जमाराशियों का पता लगाने और उन्हें वापस करने के लिए कहा है। उसने कहा है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अदावीकृत जमाराशियों / निष्क्रिय खातों के खाता धारकों का पता लगाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्हें ऐसी अदावीकृत जमाराशियों / निष्क्रिय खातों को प्रदर्शित करना चाहिए, जो 10 वर्षों या उससे अधिक अवधि से निष्क्रिय पड़े हैं। दिसम्बर 2010 में विभिन्न बैंकों में 1.03 करोड़ गैर-परिचालनात्मक खातों में 1,723.24 करोड़ रुपये की भारी रकम अदावीकृत पड़ी थी।

गृह ऋणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक का नया शिकंजा

किसी सम्पत्ति का वित्तीयन करने के लिए उसके मूल्य की गणना करते समय स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण और उसी प्रकार के प्रभारों को छोड़ देने के सम्बन्ध में बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन अधिदेश से निम्न एवं मध्यम खण्डों में मकानों की बिक्री में और कमी आने का भय व्यक्त किया जा रहा है। ऐसा भय इसलिए है, क्योंकि मकान के भावी खरीदारों को स्वयं अपनी ओर से अधिक निधियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक अब इन प्रभारों के लिए उधार नहीं देंगे।

विदेशी अंशदानों के लिए पंजीकरण "आवश्यक"

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत जारी दिशानिर्देशों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि संस्थाओं / कम्पनियों को किसी प्रकार का विदेशी अंशदान स्वीकार करने से पहले अपने आप को केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत कराना होगा। उसके बाद बैंकों को ऐसे अंतरणों की प्राप्ति से सम्बन्धित रिपोर्ट सरकार को अग्रेषित करनी होगी। इसके अलावा, प्राप्तकर्ता विदेशी अंशदान किसी एकल खाते में ही प्राप्त कर सकते हैं। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम वाले व्यक्तियों को अपने आप को किसी प्रकार का 'विदेशी अंशदान' स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकृत करवा लेना चाहिए। इसप्रकार के पंजीकरण के अभाव में वे विदेशी अंशदान को केवल केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद ही स्वीकार कर सकते हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

एटीएम वित्तीय उत्पादों का विज्ञापन कर सकते हैं

अब भारी संख्या में स्वचालित टेलर मशीने (ATMs) रखने वाले बैंक अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्तीय उत्पादों का विज्ञापन करके अतिरिक्त राजस्व सृजित करने में समर्थ हो सकते हैं। वित्तीय समावेशन को दृष्टिगत रखते हुए तथा बैंकों को दरू-दराज वाले क्षेत्रों में एटीएम खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंक-स्वाधिकृत और उसके साथ ही बाह्य-स्रोत से प्राप्त एटीएमों को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति प्रदान की है, जिन पर भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), भविष्य निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) जैसे विविध विनियामकों के अनुमोदन प्राप्त हों। विज्ञापन राजस्व से बैंकों के एटीएमों की लेनदेन लागत घटाने में समर्थ होने की आशा है।

मोबाइल बैंकिंग संवर्धन की तलाश में

अंतर-बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (IMPS) चालू हो जाने के परिणामस्वरूप बैंक अब अपने मौजूदा कारपोरेट ग्राहकों को दैनंदिन नकदी लेनदेनों को मोबाइल लेनदेनों से प्रतिस्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब तक, अपने ग्राहकों के लिए बैंकों के बीच मोबाइल निधि अंतरण को संभव बनाने हेतु 34 बैंकों ने स्वयं को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के पास पंजीकृत कराया है। इनमें से अधिकांश बैंकों ने अपने खुदरा ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवाओं की शुरूआत कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के अनुसार अंतर-बैंक मोबाइल लेनदेनों का परिमाण एक माह पहले के 4.2 करोड़ रुपये से बढ़ कर जनवरी में 5 करोड़ रुपये हो गया। लेनदेनों की संख्या उसी अवधि की 15,759 से बढ़ कर 19,101 हो गई। भारत में मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दैनिक लेनदेनों की 50,000 रुपये की सीमा को हटा दिया है।

वित्तीय वर्ष 12 में खाद्येतर ऋण वृद्धि सर्वाधिक धीमी

10 फरवरी तक के पखवाड़े में खाद्येतर ऋण वृद्धि वर्तमान वित्त वर्ष में सर्वाधिक धीमी वृद्धि की गति वर्षानुवर्ष 15.4% की दर से बढ़ी - जिससे बकाया ऋण 43,00,811 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गए। पिछले पखवाड़े में कम्पनियों और व्यक्तियों को ऋण 16.1% की वर्षानुवर्ष दर से बढ़े थे। अर्थव्यवस्था में मंदी के परिणामस्वरूप ऋणों की मांग भी कम होती जा रही है। जमाराशियों की वृद्धि दर भी धीमी पड़ती जा रही है, जो 10 फरवरी तक के पखवाड़े में केवल 14.95% की वर्षानुवर्ष दर से बढ़ी - जिससे प्रणाली में मौजूद बकाया जमाराशि 58,00,458 करोड़ रुपये रह गई। अपनी तीसरी तिमाही की समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने खाद्येतर ऋण वृद्धि से सम्बन्धित पूर्वानुमान को इसके पूर्व घोषित 18% से संशोधित करके 16% कर दिया था।

मोबाइल भुगतान सेवाओं के प्रचलन में बढ़ोत्तरी

भारतीय बाज़ार में मोबाइल भुगतान सेवाओं के प्रचलन में निरंतर रूप से बढ़ोत्तरी हो रही है। वैश्विक भुगतान कम्पनियां, बैंक, दूरसंचार विक्रेता और मोबाइल वित्तीय समाधान प्रदाता ये सब भारतीय मोबाइल भुगतान बाज़ार के एक खंड को हथियाने के इच्छुक हैं, जिसे वृद्धि के आगामी कुंड के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वे वित्तीय रूप से अल्प-सेवा प्राप्त उपभोक्ताओं की मुख्य धारा वाली वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाने में सहायता कर सकते हैं, खरीदिया, निधि अंतरण और बिलों का भुगतान अपने मोबाइल फोनों के माध्यम से कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 11 में बैंकों की सेवानिवृत्ति देयताएं बढ़कर दो गुनी

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में वाणिज्यिक बैंकों की देयताएं एक वर्ष पहले वाली अवधि में 6,154 करोड़ रुपये से बढ़कर 31 मार्च, 2011 के दिन 10,500 करोड़ रुपये के रूप में दो गुनी हो गई हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उनके वित्त के समक्ष देयताओं की सीमा तक के सबसे बड़े जोखिम का सामना किया जा रहा है। बीएसई -100 वाली सभी कम्पनियों में कर्मचारियों के लाभों के रूप में संयुक्त अनुमानित देयताएं एक वर्ष पहले की अवधि में 2 लाख करोड़ रुपये से 45% बढ़कर 31 मार्च, 2011 के दिन 2.90 लाख करोड़ रुपये हो गईं।

विदेशी बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त उधारों को बढ़ाना चाहिए

श्री एम.वी. नायर समिति की सिफारिशों के अनुसार भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को उन्हें घरेलू ऋणदाताओं की अनिवार्य अपेक्षाओं के समकक्ष लाते हुए उनके कुल ऋण संविभाग का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए अलग रखना चाहिए। उक्त पैनल ने यह भी सुझाव दिया है कि महिलाओं को प्रदत्त ऋणों को कमजोर वर्गों को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वर्तमान में विदेशी बैंकों के लिए उनके 32% ऋण किसानों, छोटे व्यवसायियों, विद्यार्थियों, समाज के कमजोर वर्गों सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना जरूरी नहीं है। विदेशी ऋणदाताओं को निर्यातकों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को अनिवार्य रूप से 15% उधार देना चाहिए। उन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 40% ऋण देने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए।

निजी क्षेत्र के सभी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के एजेन्ट

अब निजी क्षेत्र के सभी बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की भांति ही भारतीय रिज़र्व बैंक के एजेन्टों के रूप में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कामकाज संभालने के पात्र होंगे। अब तक निजी क्षेत्र के केवल 3 बैंकों, यथा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और ऐक्सिस बैंक को ही यह

सुविधा प्राप्त थी। इस कार्रवाई से ग्राहक सेवा केन्द्रों की संख्या बढ़ा कर और सरकारों की राजस्व वसूली एवं भुगतान व्यवस्था को व्यापक आधार वाली बना कर ग्राहक सुविधा में सुधार होगा।

ग्राहकों के विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों की जांच करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से संभाव्य ऋण हानियों को कम करने के लिए ग्राहकों के अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों कां "कठोरतापूर्वक मूल्यांकन करने" तथा ऋण सुविधाओं का मूल्य-निर्धारण तदनुसार करने के लिए कहा है। इसके अतिरिक्त बैंकों को उनके निदेशक मण्डलों द्वारा अनुमोदित नीतियों के आधार पर कम्पनियों की अप्रतिरक्षित स्थितियों के सम्बन्ध में एक सीमा विनिर्दिष्ट करने पर भी विचार करना चाहिए। वर्तमान में बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे बड़े ग्राहकों के अप्रतिरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की प्रति माह समीक्षा करें। भारतीय रिज़र्व बैंक का मत यह है कि मुद्राओं में तीव्र प्रतिकूल उतार-चढ़ाव होने की स्थिति में कम्पनियों द्वारा अपेक्षा से अधिक जोखिम उठाए जाने के कारण उन्हें गंभीर विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है और उनके बैंकरों को भारी मात्रा में संभाव्य ऋणगत हानि उठानी पड़ सकती है।

वैयक्तिक ऋणों में वृद्धि धीमी पड़ कर 12.3% हुई

भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त क्षेत्रवार ऋण आंकड़ों से यह पता चलता है कि वैयक्तिक ऋणों में वृद्धि धीमी पड़ कर नवम्बर में दर्ज 23.4% की वर्षानुवर्ष दर से घट कर दिसम्बर में 12.3% के वर्षानुवर्ष स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल, 2011 से, जब इस श्रेणी को प्रदत्त ऋणों में 18% से अधिक की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई थी, हर बीते माह में यह वृद्धि कमतर होती गई है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को प्रदत्त ऋणों में भी कुछ कमी आई है, जो नवम्बर में वर्षानुवर्ष 39.2% की तुलना में दिसम्बर में घट कर वर्षानुवर्ष 36.2% रह गए।

भारतीय रिज़र्व बैंक 1,000 रुपये के मूल्यवर्ग वाले नोट जारी करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक शीघ्र ही गैर-क्रमांकित संख्या में 1,000 रुपये के मूल्यवर्ग वाले नोट जारी किए जाने की शुरूआत करेगा। इन पैकेटों में से प्रत्येक में 100 नोट रहेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को बाह्य वाणिज्यिक उधार निधियों के अंतिम उपयोग के सम्बन्ध में अधिकार प्रदान किए

अब भारतीय कम्पनियों के बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) में बैंकों की भूमिका महत्तर होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को इस आशय के अधिकार प्रदान किए हैं कि वे बाह्य वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अंतिम उपयोग में अनुरोध को उसे प्रेषित किए बिना ही परिवर्तन

कर सकते हैं। अब बैंक स्वत: मार्ग के अधीन अपतटीय वाणिज्यिक उधारों के अंतिम उपयोग को परिवर्तित करने के किसी फर्म के अनुरोध को अनुमोदित कर सकते हैं। बैंक इसे विदेशी निधि संग्रहण कार्यविधि के युक्तिसंगत बनाए जाने तथा प्रशासनिक अड़चनों की समाप्ति के रूप में देखते हैं। हालांकि, अनुमोदित मार्ग के तहत जुटाई गई निधियां अब भी भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग को संदर्भित की जानी होंगी । भारतीय रिज़र्व बैंक ने 750 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक वाले बाह्य वाणिज्यिक उधारों का मामला-दर मामला आधार पर अनुमोदन प्रदान किया है।

बॉण्डों के प्रतिफल 9-माह के न्यूनतम स्तर पर

इस आशा के आधार पर कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाने वाली ऋण खरीदियों से नकदी संकुचन में कमी आएगी, 1 फरवरी 2012 को प्रतिफल को 9 माह के सबसे निचले स्तर पर पहुंचाते हुए 10 वर्षीय सरकारी बॉण्डों मे तेजी आ गई। मौद्रिक प्राधिकारी, जिसने नवम्बर से 71,900 करोड़ रुपये के नोट खरीदे हैं, खुले बाज़ार के परिचालनों में ऋण खरीदने से विरत रहा। 8.79% वाले (नवम्बर 2021 में देय) नोटों से सम्बन्धित दर 14 आधार अंक गिर कर 8.13% रह गई। यह 28 अप्रैल, 2011 से किसी बेंचमार्क 10 वर्षीय बॉण्ड का न्यूनतम स्तर है। 1वर्षीय ब्याज दर अदला-बदली (swaps) [अर्थात् निधीयन लागतों में उतार-चढ़ावों से बचने के लिए प्रयुक्त होने वाली व्युत्पन्नी संविदा] की लागत 5 आधार अंक घट कर 8.11% हो गई। पिछले तीन महीनों में कमियों को पूरा करने के लिए ऋणदाताओं ने भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रति दिन औसतन 1.1 लाख करोड़ रुपये (इसके पहले वाली अवधि में 51,500 करोड़ रुपये से अधिक) उधार लिये।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार पैनल लक्ष्य को 40% से घटा सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के 40% के लक्ष्य को युग्मित करने पर विचार कर सकता है। हालांकि, बैंकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और कमजोर वर्गों को अधिक उधार देना पड़ सकता है। हितधारकों से प्राप्त प्रति-सूचना के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक कमजोर वर्गों को आवासीय वित्त को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारों के तहत श्रेणीकृत किए जाने पर विचार कर सकता है। बैंकों के लिए इस क्षेत्र को उधार देने की अनिवार्यता के बावजूद प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारों में वृद्धि 2009-10 में 29.2% से कम हो कर 2010-11 में केवल 5% रह गई है।

विनियामकों के कथन

भारतीय रिज़र्व बैंक अनर्जक आस्तियों के प्रावधानीकरण के सम्बन्ध में एकमुश्त रियायत नहीं दे सकता

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि "वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को अनर्जक आस्तियों के प्रावधानीकरण के रूप में एकमुश्त रियायत देने पर विचार नहीं कर रहा है। हम बढ़ती अनर्जक आस्तियों और ऋण पुनर्व्यवस्था की प्रवृत्ति के बावजूद बैंकों के लिए कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं करने जा रहे हैं।" इसके पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक बार 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में कम्पनियों को चुकौती के दबाव से मुक्ति दिलाने के लिए एकमुश्त रियायत प्रदान की थी।

चलनिधि घाटे में अभी तक भारतीय रिज़र्व बैंक की सहूलियFEDAIत के स्तर तक कमी नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि जहां आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में कमी के संयोजित प्रभाव और खुले बाज़ार के परिचालनों के संचयी प्रभाव के कारण चलनिधि सम्बन्धी दबाव में कमी आनी शुरू हो गई है, वहीं आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी और खुले बाज़ार के परिचालनों से चलनिधि घाटे में कमी सहूलियत के स्तरों तक नहीं आ पाई है। फलत: शीर्ष बैंक द्वारा सरकारी बॉण्डों की वापसी खरीद अथवा खुले बाज़ार के परिचालनों का क्रम और आगे भी जारी रखा जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के विदेशी मुद्रा लिखतों के क्रय-विक्रय की सीमा शिथिल की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसम्बर में रुपये के मूल्य में भारी गिरावट की पृष्ठभूमि में लागू की गई बैंकों की विदेशी मुद्रा लिखतों के क्रय-विक्रय सीमाओं को शिथिल कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान ने यह कहते हुए इसकी पुष्टि की है कि "यदि बैंकों को आवश्यकता हो, तो वे अपने निदेशक मण्डल की अनुमति के साथ भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI) के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इन छूटों की आवश्यकता क्यों और कितनी रकम के लिए है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक सरकार के उधार लेने की योजना के प्रति उदासीन नहीं रह सकता

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि " भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति का लक्ष्य-साधक अथवा मुख्य मुद्रास्फीति लक्ष्य-साधक नहीं हो सकता। उससे देश के स्थूल-आर्थिक प्रबन्धन के सर्वोत्तम हित साधन नहीं होगा।" उन्होंने यह भी कहा कि शीर्ष बैंक किसी ऐसी नीति का अनुसरण नहीं कर सकता, जो वृद्धि के प्रति पूर्णरूपेण विस्मरणशील हो। बढ़ते सरकारी उधारों के सम्बन्ध में डॉ. सुब्बाराव ने कहा कि मौद्रिक नीति के लिए यह संभव नहीं हो सकता कि वह सरकार के उधार लेने के कार्यक्रमों के प्रति "उदासीन" बनी रहे।

दर में भारी कमी नहीं, खुले बाज़ार के परिचालन जारी रहेंगे

आर्थिक वृद्धि के मंद पड़ती लगने और मुद्रास्फीति में कमी की शुरूआत हो जाने के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दरों में भारी कमी किए जाने की संभावना नहीं है। आर्थिक वृद्धि में उतार-चढ़ाव होने के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दरों को जनवरी 2012 से लगातार दो महीनों से अपरिवर्तित रखा है। हालांकि, पिछले माह में प्रणाली में 32,000 करोड़ रुपये की प्राथमिक चलनिधि बढ़ाने के लिए उसने आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में 50 आधार अंकों की कमी कर दी थी। डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह कहते हुए कि "जब हमें यह लगेगा कि ये उपाय अब आवश्यक नहीं रह गए हैं, हम स्थिति को वहीं वापस पहुंचाएंगे जहां वह थी। इस अर्थ में वे

अस्थायी हैं" , इस बात का संकेत दिया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक चलनिधि की कठिन स्थिति से निपटने के लिए खुले बाज़ार के परिचालन जारी रखेगा ।

बीमा

इर्डा ने स्वास्थ्य बीमा मंच गठित किया

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने सभी हितधारकों के लिए परामर्शी निकाय के रूप में काम करने हेतु स्वास्थ्य बीमा मंच का गठन किया है। इस पहलकदमी के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री जे. हरि नारायण कहते हैं, स्वास्थ्य बीमा उद्योग में हुए विकास को देखते हुए यह जरूरी समझा गया कि अस्पतालों, बीमा कम्पनियों, अन्य पक्ष के प्रशासकों और उपभोक्ताओं के बीच एक प्रभावी संवाद की स्थिति निर्मित की जाए। उक्त मंच स्वास्थ्य बीमा विनियमन तैयार करने में विनियामक को सलाह एवं सहायता प्रदान करेगा तथा स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में मानक प्रक्रियाओं एवं परिभाषाओं के सृजन और अंगीकरण को सुगम बनाएगा।

बीमा एजेन्टों के लिए इर्डा की शिक्षण निर्देशिका

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) एजेन्टों को "सलाहकारों" के रूप में दीक्षित करने के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ है और विस्तृत दिशानिर्देशों का एक ऐसा प्रारूप तैयार कर रहा है जो जीवन बीमा पॉलिसी की बिक्री को "आवश्यकता" अथवा "उपयुक्तता" पर आधारित बना देगा। इसका उल्लिखित आशय यह है कि किसी बीमा उत्पाद का चयन करने का सवाल उठने पर वह केवल पॉलिसी धारकों की ही जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके बजाय वह एजेन्टों द्वारा संस्तुत पॉलिसी धारक की प्रोफाइल पर निर्भर करेगा। इन दिशानिर्देशों का अन्तर्निहित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई एजेन्ट किसी ऐसे उत्पाद को जबरन थोपने में समर्थ न हो जिसमे कमीशन अधिक हो।

इर्डा बीमित राशि पर ऊपरी सीमा के पक्ष में

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने जीवन बीमा पॉलिसियों पर बीमित रकम की अधिकतम सीमा नियत करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बीमाकर्ता बीमा दावों का भुगतान करने के लिए पुनर्बीमा कम्पनियों पर अत्यधिक निर्भर रहने के बजाय अधिकतम जोखिम स्वयं ही उठाएं।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए सकारात्मक संकेत

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारो (PSL) पर एम.वी. नायर समिति ने यह सिफारिश की है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक ऋण का 5% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने पर अब भी निधियों की कमी का सामना कर रही गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को महत्वपूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होने के अवसर हैं। सा-धन के कार्यपालक निदेशक श्री मैथ्यू टाइटस का कहना है कि "अच्छी गुणवत्ता वाले ऋण पोर्टफोलियो पाना बैंकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां यद्यपि छेटे आकार वाले ऋण प्रदान करती हैं, तथापि वे अधिकांशतया अच्छी गुणवत्ता वाली होती हैं। यह उन गैर-वित्तीय एजेन्सियों के लिए भी एक नया अवसर होगा जो पोर्टफोलियों का विशुद्ध रूप से प्रवर्तन करने और उसे बैंकों को सौंप देने के इस व्यवसाय में प्रवेश करने की इच्छुक हों।"

अर्थव्यवस्था

आर्थिक वृद्धि 8.4% के रूप में घटा कर संशोधित

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) ने वर्ष 2010-11 के लिए देश के सकल धरेलू उत्पाद वृद्धि के अपने अनुमानों को पहले के 8.5% से घटा कर 8.4% कर दिया है। उसने 2009-10 के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के अनुमानों को भी ऊर्ध्वमुखी संशोधन करते हुए पहले के 8% से 8.4% कर दिया है। अद्यतन संशोधन 2010-11 के राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के त्वरित अनुमानों के अंग हैं।

बचत की वृद्धि मंद हुई, वृद्धि खतरे में पड़ी

भारत की अर्थव्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष में अधिक तीव्र गति से वृद्धि दर्ज कर सकती है, किन्तु बचतों में मंदी की प्रवृत्ति उसे 2011-12 में सरकार द्वारा अपेक्षित 7.2% से पर्याप्त रूप से अधिक की दर से बढ़ने से रोक सकती है। उच्च मुद्रास्फीति के कारण बचतों में वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू बचतों के अंश में 1.5% की कमी लाते हुए घट कर पिछले वर्ष की 21% की तुलना में 2010-11 के दौरान 13.7% के स्तर पर आ गई। बचतों की उच्च दर के कारण भारत घरेलू स्तर पर अपने निवेशों के काफी बड़े अंश का वित्तीयन करने में समर्थ हो सका और बचतों में गिरावट से संभाव्य वृद्धि दर - वह संख्या जो अर्थव्यवस्था के पूरे वितान में परिचालित होने पर प्राप्य है- में कमी आ सकती है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 369 मिलियन अमरीकी डालर की गिरावट

भारतीय रिज़र्व बैंक की साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट के अनुसार 10 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां 369.2 मिलियन अमरीकी डालर घट कर 293.383 बिलियन अमरीकी डालर रह गईं। यह गिरावट मुख्यत: मुद्रा के पुनर्मूल्यन के कारण आई। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में गिरावट आई है। विचाराधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियों में 370.6 मिलियन अमरीकी डालर की गिरावट आई, जिसके फलस्वरूप वे 259.446 बिलियन अमरीकी डालर रह गईं। सोना 26.727 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर अपरिवर्तित रहा। विशेष आहरण अधिकारों (SDRs) में 0.6 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई जिससे वे 4.474 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में देश की स्थिति में 0.8 मिलियन डालर की वृद्धि हुई और वह 2.734 बिलियन हो गई।

प्रलेखन रहित आयात के लिए विदेशी मुद्रा की सीमा बढ़ाकर 5000 अमरीकी डालर की गई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यक्तियों, फर्मों और कम्पनियों द्वारा प्रलेखन सम्बन्धी किसी औपचारिकता के बिना आयात हेतु विदेशी मुद्रा जारी किए जाने की सीमा 500 अमरीकी डालर या उसके समकक्ष रकम से बढ़ाकर 5000 अमरीकी डालर या उसके समकक्ष रकम कर दी गई है। विदेशी मुद्रा का लेनदेन करने हेतु प्राधिकृत बैंकों को जब तक खरीदी जा रही विदेशी मुद्रा किसी चालू खाते के लेनदेन के लिए हो, आवेदक से उस एक पत्र को छोड़कर जिसमें आवेदक के नाम और पते, लाभार्थी के नाम और पते, विप्रेषित की जाने वाली रकम और विप्रेषण का उद्देश्य जैसी मूलभूत सूचनाएं दी गई हों, किसी प्रकार का प्रलेख प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

डालर के अन्तर्वाहों के फलस्वरूप 49.27 पर रुपया 3-माह के उच्चतर स्तर पर

डालर के सुदृढ़ अन्तर्वाहों, स्थानीय शेयरों में मज़बूती और यूरो में पुनरुत्थान से बल पा कर पूर्ववती सभी हानियों की भरपाई करते हुए 1 फरवरी को रुपया लगभग 3 माह के उच्चतर स्तर पर पहुंच गया। दिन के 49.55 के न्यून स्तर से उछल कर - इसके पहले वाले दिन के 49.44 / 45 के बंद भाव से 0.4% मजबूत होते हुए रुपया 49.2650 / 2750 पर बंद हुआ। रुपये से सम्बन्धित प्रत्याशा में तेजी का रुख बना रहा, क्योंकि विदेशी निवेशकों द्वारा एशिया की उस तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में और भी निधियों का निवेश किए जाने की आशा है, जिसमें वृद्धि सिर उठाती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक क्रमिक रूप से एक समंजनशील मौद्रिक नीति की ओर वापस आ रहा है।

मार्च 2012 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.05980	0.560	0.681	0.867	1.092
जीबीपी	1.88302	1.2361	1.2935	1.3996	1.5466
यूरो	1.59571	1.123	1.209	1.360	1.550
जापानी येन	0.55371	0.353	0.369	0.406	0.465
कनाडाई डालर	1.89300	1.289	1.401	1.527	1.657
आस्ट्रेलियाई डालर	4.96000	4.230	4.255	4.453	4.535
स्विस फ्रैंक	0.34117	0.105	0.168	0.265	0.390
डैनिश क्रोन	1.57800	1.2030	1.2950	1.4590	1.6490
न्यूजीलैंड डालर	3.54400	3.090	3.325	3.558	3.785
स्वीडिश क्रोनर	2.86200	1.990	2.011	2.100	2.195

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	**17 फरवरी 2012 के दिन**	**17 फरवरी 2012 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियां	14, 452, 80	293,439.70
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	12,771. 70	259, 534.30
ख) सोना	1, 327, 80	26, 727.60
ग) विशेष आहरण अधिकार	2 19, 3	4, 455.60
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	134	2, 722.20

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

नयी नियुक्तियां

- श्री एस.एल. बंसल को ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री एम.जी. संघवी को सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री अमर लाल दौलतानी को कारपोरेशन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री सुनील कौशल को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भारत और दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय मूक्य कार्यपालक के रूप में नियुक्त किया गया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
येस बैंक	बुल्डाना सोसाइटी	अपनी नयी ग्राहक पहलकदमी से सोसाइटी की दरवाजे पर पर-बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में सहायता करना।
बिड़ला सनलाइफ	सिंडिकेट बैंक	बिड़ला सनलाइफ को भारतभर में फैली बैंक की शाखाओं तक पहुंच प्राप्त होगी, जबकि वह बैंक के लिए जीवन बीमा क्षेत्र में अल्पसंख्यक हित की प्राप्ति सुनिशचित करेगी।
टाटा कैपिटल	ऐक्सिस बैंक	एक ऐसे यात्री कार्ड की संयुक्त रूप से शुरूआत की गई, जो वीसा प्लेटफार्म पर 9 मुद्राओं में उपलब्ध है। इसका उपयोग 26 मिलियन से अधिक बिक्री केन्द्रों और 1.9 मिलियन वीसा एटीएमों पर तथा सभी विदेशी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर किया जा सकता है।
दि करूर वैश्या बैंक लिमिटेड	एसबीआई काड्र्स	सह-ब्रॉण्ड वाले क्रेडिट कार्डों की शरूआत की। वह एसबीआई काड्र्स पोर्टफोलियो को तैयार और तत्काल पहुंच प्रदान करेगा। उक्त कार्ड में एक चुंबकीय पट्टी और एक चिप लगी है, जो कार्ड धारकों को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान करेगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा	केयर (CARE)	ऐसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के साख श्रेणी-निर्धारण के लिए जो या तो बैंक के संभाव्य या फिर मौजूदा ग्राहक हैं।
बैंक ऑफ इंडिया	न्यूयार्क स्थित माइक्रो एनर्जी क्रेडिट कारपोरेशन	ग्रामीण उधारकर्ताओं को हरित समाधान कार्यान्वित करने और कार्बन ऋण प्राप्त करने में सहायता करना
ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड	खुदरा आस्तियों का समनुदेशन

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश :)

अंतराष्ट्रीय निपटान बैंक के प्रभावी बैंक पर्यवेक्षण के मुख्य सिद्धांतों के सारांश प्रस्तुत करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हम अपने पाठकों को कुछ और जानकारी प्रदान कर रहे हैं :

1. वर्तमान में, मुख्य सिद्धांतों के अनुपालन का कोटि-निर्धारण केवल अनिवार्य मानदंडों पर आधारित है। अधिकार-क्षेत्रों, विशेष रूप से उन्हें, जो महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्र हैं, को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वोच्च पर्यवेक्षी मानकों के अंगीकरण में सबसे आगे रहने के लिए संशोधित मुख्य सिद्धांत देशों को अनिवार्य एवं अतिरिक्त मानदंडों के आधार पर स्वैच्छिक रूप से मूल्यांकित एवं कोटि-निर्धारित किए जाने का विकल्प चुनने का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराते हैं।पूर्ण और सुदृढ़ कार्यान्वयन को बढ़ावा देने की उसी भावना से समिति ने मुख्य सिद्धांतों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए मौजूदा चारश्रेणियों वाले मान को बनाए रखा है। इसमें वह वर्तमान "भौतिक रूप से अननुपालनीय" श्रेणी भी शामिल है, जो सम्बन्धित प्राधिकारियों को उनके देशों में पर्यवेक्षी और विनियामक कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक उपचारात्मक उपायों के सम्बन्ध में एक सुदृढ़ संकेतात्मक प्रभाव उपलब्ध कराने में सहायता करती है।
2. इस समीक्षा के परणिामस्वरूप मुख्य सिद्धांतों की संख्या 25 से बढ़ कर 29 हो गई है। कुल मिलाकर 36 नये मूल्यांकन मानदंड हैं, जिनमें 31 नये अनिवार्य मानदंडों और 5 नये अतिरिक्त मानदंडों का समावेश है। इसके अलावा, मौजूदा मूल्यांकन कार्यप्रणाली से 33 अतिरिक्त मानदंडों का कोटि-उन्नयन कर के उन्हें ऐसे अतिरक्त मानदंडों का दर्जा दे दिया गया है, जो सभी देशों की न्यूनतम आधार-रेखा आवश्यकताओं का निरूपण करते हैं।
3. ये संशोधित मुख्य सिद्धांत बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन, पर्यवेक्षण, अभिशासन और जोखिम प्रबन्धन के लिए एक सुदृढ़ आधार निर्मित करने के लिए एक व्यापक मानक उपलब्ध कराते रहेंगे। सुसंगत और प्रभावी मानकों के कार्यान्वयन के महत्व को देखते हुए समिति इन संशोधित मुख्य सिद्धांतों को अन्य

पर्यवेक्षी निकायों और रुचि रखने वाले पक्षकारों की संहति में राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु हमेशा तत्पर रहती है।
(स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

प्रौद्योगिकी बुलयुला (Tech bubble)

प्रौद्योगिकी शेयरों में बढ़ी हुई सट्टेबाजी (अटकलों) के कारण उच्चारित एवं अस्थिर बाज़ार वृद्धि। प्रौद्योगिकी बुलबुला शेयर की कीमत में तीव्र वृद्धि तथा कीमत / अर्जन अनुपात अथवा कीमत / बिक्री जैसे मानक मेट्रिक्सों के आदार पर उच् मूल्यांकनों द्वारा प्रकाश में आता है। किसी बुलबुले में सम्मिलित प्रौद्योगिकी शेयर निवेशक मांग की शक्ति और गहनता के आधार पर (इंटरनेट सॉफ्टवेयर अथवा ईंधन सेलों जैसे किसी विशिष्ट उद्योग तक सीमित हो सकते हैं अथवा सम्पूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्र तक व्याप्त हो सकते हैं। किसी बुलबुले के शिखर पर होने पर कई एक उभरती प्रौद्योगिकी कम्पनियां बढ़ी हुग्निवेशक मांग का लाभ उठाने के प्रयास में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPO) के माध्यम से सार्वजनिक होने का प्रयास करेंगी।

शब्दावली

कार्बन क्रेडिट

एक ऐसा अनुज्ञा पत्र (परमिट) जो धारक को एक टन कार्ब डाईऑक्साइड उत्सर्जित करने की अनुमति देता है। ये अनुमतियां (क्रेडिटें) उन देशों अथवा समूहों को प्रदान की जाती हैं, जिन्होंने अपनी ग्रीन हाउस गैसों को घटा कर अपने उत्सर्जन कोटे के स्तर से कम कर दिया है। कार्बन क्रेडिटों को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में उनके वर्तमान बाज़ार मूल्य पर खरीदा-बेचा जा सकता है।

संस्थान की गतिविधियां

लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, कुर्ला में प्रशिक्षण गतिविधियां
टॉपसिम - सर्वव्यापी बैंकिंग अनुरूपण कार्यक्रम

संस्थान ने 27वीं और 28वीं फरवरी 2012 को टाटा इंटरऐक्टिव सिस्टम्स के सहयोग से टॉपसिम-सर्वव्यापी बैंकिंग अनुरूपण पर दूसरे (2रे) द्वि-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। उक्त कार्यशाला में 17 सहभागियों ने भाग लिया।

वित्तीय समावेशन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान ने 17वीं और 18वीं फरवरी 2012 को सिंडिकेट बैंक प्रबन्धन संस्थान , मणिपाल में सिंडिकेट बैंक के प्रशित्रण प्रबन्धकों के लिए एक 2 दिवसीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया था। उक्त प्रशिक्षण में 27 सहभागियों ने भाग लिया।

संस्थान समाचार

ग्राहक सेवा पर संगोष्ठी

- संस्थान ने 28 फरवरी, 2012 को अहमदाबाद में 'ग्राहक सेवा' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री सुदर्शन सेन द्वारा किया गया तथा मुख्य व्याख्यान भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड के अध्यक्ष श्री ए.सी महाजन द्वारा दिया गया। उक्त संगोष्ठी में 120 सहभागियों ने भाग लिया।

- संस्थान ने 5 मार्च 2012 को चेन्नै में 'ग्राहक सेवा' पर दूसरे व्याख्यान का आयोजन किया। मुख्य व्याख्यान भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री विश्वनाथन द्वारा दिया गया और समापन व्याख्यान भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री नारायण राजा द्वारा दिया गया। उक्त संगोष्ठी में 80 सहभागियों ने भाग लिया।

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। (विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।)

जेएआईआईबी / डीबीऐण्ड एफ और सीएआईआईबी के अभ्यर्थियों के लिए वेब कक्षाएं और ई-शिक्षण

संस्थान जेएआईआईबी / डीबीऐण्ड एफ और सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों के लिए वेब कक्षाओं और ई-शिक्षण की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। (विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।)

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन
पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

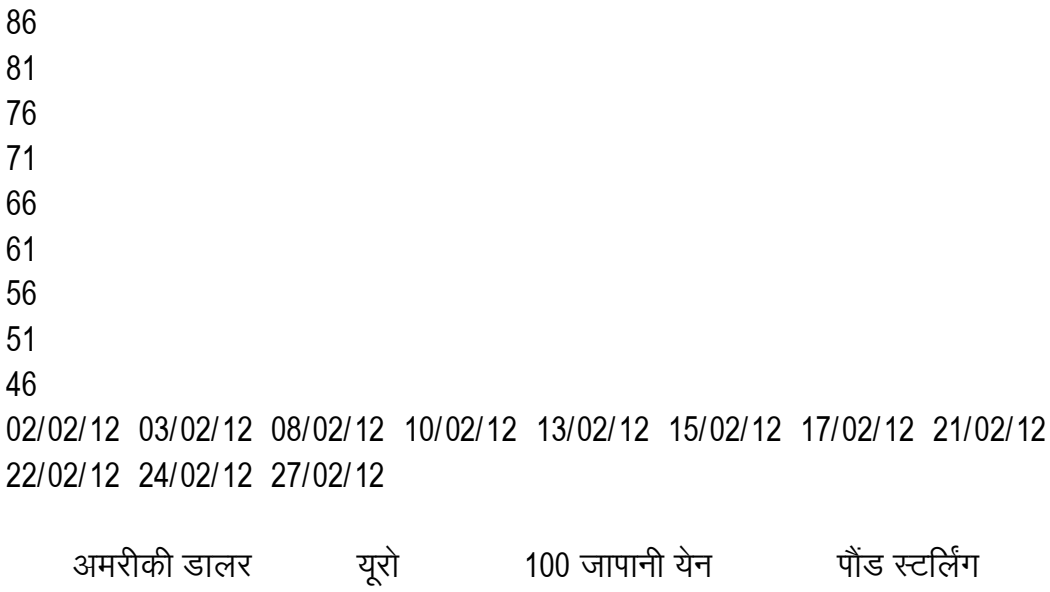

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- घरेलू इक्विटियों में मज़बूतियों से प्रोत्साहित हो कर रुपया 2री को तीन-माह के उच्च स्तर पर पहुंच कर 49.15 /16 पर बंद हुआ।
- वर्धित विदेशी निधि प्रवाहों और मौद्रिक सहजता की आआशाओं ने मुद्रा को मजबूती दी। 3री को रुपया डालर के मुकाबले 48.6850 / 6950 पर बंद हुआ, जो एक ऐसा स्तर था, जो 31 अक्तूबर से देखने में नहीं आया ।
- बैसिक्स फॉरेक्स के निदेशक के अनुसार जनवरी के व्यापार घाटे के 14.7 बिलियन डालर होने के परिणामस्वरूप मार्च 2012 के अंत में चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% रहने की संभावना है, फिर 13वीं से प्रारंभ होने वाले सप्ताह के दौरान रुपये के 49.20 - 50.25 की मूल्य पट्टी के बीच खरीदे -बेचे जाने की संभावना है।
- सेन्ट्रम डायरेक्ट के खज़ाने प्रमुख के अनुसार अमरीकी डालर - रुपया युग्म के यूरो क्षेत्र में मुख्यत:स्थिरता के कारण मूल्यवृद्धि वाले रुख में खरीदे-बेचे जाने की संभावना है। इसके 48.60 और 49.50 के बीच खरीदे - बेचे जाने की संभावना है।
- 28वीं को स्थानीय स्टॉक और ऋण वाज़ार में पूंजी प्रवाहों के फलस्वरूप निवेशक की जोखिम भूख बढ़ जाने के परिणामस्वरूप रुपये में मूल्यवृद्धि हुई,क्योंकि ग्रीस के ऋण संकट के प्रति चिंता में कमी आ गई।
- माह के दौरान डालर के समक्ष रुपया 1.61%बढ़ा।

- यूरो के मुकाबले माह के दौरान रुपये मेंएक दिन के 17.95% के मूल्यह्रास और अगले दिन के 16.22% के मूल्यह्रास के साथ 0.17% का मूल्यह्रास हुआ
- स्टर्लिंग और जापानी येन के मुकाबले मूल्यवृद्धि की प्रवृत्ति रही।

भारित औसत मांग दरें

9.00
8.90
9.80
8.70
8.60
8.50
8.40
8.30

01/02/12 04/02/11 06/02/12 08/02/12 10/02/12 11/02/12 13/02/12 15/02/12
18/02/12 21/02/12 23/02/12 24/02/12

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जनवरी , 2012

- मांग दरें प्राणाली में चलनिधि के आधिक्य के फलस्वरूप वापस गिर गईं। एक-दिवसी मुद्रा के मांग बाज़ार में अधोमुखी प्रतिक्रिया हुई जिससे वह 1ली को 8.90% से घट कर 8.75% पर बंद हुआ। वह 9.05% से 8.50% की श्रेणी के बीच घटती-बढ़ती रही।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी के बाद पहले पखवाड़े के अंत में प्रणाली की चलनिधि में सुस्पष्ट वृद्धि परिलक्षित हुई, क्योंकि औसत चलनिधि समायोजन सुविधा की संख्या घट कर 1.18 ट्रिलियन रुपये रह गई और मांग दर 9% से कम के स्तर पर रही। विश्लेषकों के अनुसार आगामी मांग दरों के 8.75% और 9% के बीच मंडराते रहने की आशा है।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

18400
18200
18000
17800
17600
17400
17200

01/02/12 02/02/12 03/02/12 08/02/12 09/02/12 13/02/12 16/02/12 17/02/12
23/02/12 24/02/12 27/02/12 28/02/12

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न मार्च, 2012